30 जून 2017

नियंत्रण व्यवस्था में भारत का आगे का रास्ता: परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता के लिए भारत की इच्छा का एक विश्लेषण

शाइस्ता निशात अहमद

प्रस्तावना

भारत परमाणु और तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था और विशेष रूप से 2008 के सितंबर में एनएसजी दिशानिर्देशों से छूट दिए जाने के बाद से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में सदस्यता प्राप्त करने की कोशिश में है। यह छूट, 1974 में पोखरण में पहले भारतीय परमाणु परीक्षण के बाद लगाये गये , भारत के साथ असैनिक परमाणु व्यापार पर पिछले प्रतिबंध को समाप्त कर देती है, क्योंकि यह भारत को अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में काफी विस्तार करने और आने वाले वर्षों में निर्यात बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देती है। यद्यपि 2008 के एनएसजी की छूट, भारत के लिए अन्य देशों के साथ असैनिक परमाणु व्यापार में संलग्न होने की महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करती है (और वास्तव में, भारत ने रूस, फ्रांस, यूके, यूएसए, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों के साथ इस तरह के समझौते किए हैं) एनएसजी की सदस्यता भारत के परमाणु शासन के लिए अधिक निश्चितता और कानूनी आधार प्रदा न करेगी और इस प्रकार उन देशों के लिए अधिक विश्वास उत्पन्न होगा जो भारत में महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा, जैसे-जैसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक प्रोफ़ाइल और जोर बढ़ रहा है, भारत नियम-पालन करने वाले देशों की श्रेणी में रहने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने वाले देशों की श्रेणी में जाना चाहता है। इसके लिए, यह आवश्यक है कि भारत को उचित मान्यता और एनएसजी के उच्च पटल पर जगह मिले।

मूल रूप से वहां आयोजित होने वाली प्रारंभिक बैठकों की अधिकता के कारण मूल रूप से "लंदन क्लब" कहा जाने वाला एनएसजी, एक संधि नहीं थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा समूह था जिसने कुछ दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देने और परमाणु और रेडियोधर्मी सामग्री के व्यापार और निर्यात को विनियमित करने और दोहरी उपयोग प्रौद्योगिकी के संचालन पर काम किया। एनएसजी बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य "परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के अंतर्गत गैर-परमाणु हथियार वाले राज्यों (एनएनडब्ल्यूएस) के रूप में परिभाषित राज्यों को ऐसी प्रौद्योगिकियों की

आपूर्ति के लिए अपने राष्ट्रीय नियमों के समन्वय करने" के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के स्वामित्व वाले देशों की देखरेख करना था।[1] इसका उद्देश्य "यह सुनिश्चित करना है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु व्यापार, परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु विस्फोटक के प्रसार में योगदान नहीं करता है और परमाणु क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग इस प्रक्रिया में अन्यायपूर्ण रूप से बाधा नहीं है।"[2]

एनएसजी दो विशिष्ट दिशानिर्देशों के संचालन के माध्यम से कार्य करता है। एनएसजी दिशानिर्देशों का पहला सेट उन वस्तुओं के निर्यात की देखरेख करता है, जो विशेष रूप से परमाणु सामग्री , परमाणु रिएक्टर और उनके लिए उपकरण , गैर-परमाणु सामग्री के लिए रिएक्टर और परमाणु सामग्री के पुनर्संसाधन, संवर्धन और रूपांतरण के लिए संयंत्र व उपकरण और ईंधन निर्माण और भारी जल उत्पादन , जैसे परमाणु उपयोग और उपरोक्त श्रेणियों में से प्रत्येक की तकनीक के साथ जुड़े हैं। दिशानिर्देशों का दूसरा सेट परमाणु-संबंधित दोहरे उपयोग की वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करता है, जो एक असुरक्षित परमाणु ईंधन चक्र या परमाणु विस्फोटक गतिविधि में प्रमुख योगदान दे सकते हैं , लेकिन इसके औद्योगिक परिदृश्य जैसे गैर-परमाणु उपयोग भी हैं। इसके अतिरिक्त, ये दिशा-निर्देश एनपीटी या इसी तरह के अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी क्षेत्रीय संधि यों के भी अनुरूप हैं, जो परमाणु अप्रसार के विषय में हैं , जैसे कि पेलिंडाबा, बैंकाक, सेमिलिपलाटिंस्क, रारोटोंगा, और टॉलिसोलको की संधियाँ। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास को आगे बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में , एनएसजी के प्रतिभागियों की आपूर्ति की सूक्ष्म शर्तों का पालन करने की प्रतिबद्धता एनएसजी को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व बनाती है।[3] इस प्रावधान ने गैर-एनपीटी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग का लाभ प्राप्त करने के लिए उसमें प्रवेश को मुश्किल बना दिया। लेकिन 2001 में, एस्पेन प्लेनरी में क्लब में नए सदस्यों को समायोजित करने के पिछले दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था। इसके अनुसार, एनपीटी की सदस्यता को केवल एनएसजी में आवेदन करने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में लिया जाना था , न कि अनिवार्यता के रूप में जैसा कि पहले था।[4]

एनएसजी छूट एक तरह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु सक्षम देश के रूप में स्वीकार करती है और अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में भारत की छवि को बढ़ावा देती है। लेकिन इसके बावजूद, भारत अभी तक परमाणु हथियार सम्पन्न राज्य (एनडब्ल्यूएस) के रूप में पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है। इस छूट ने भाग लेने वाली सरकारों के लिए ट्रिगर सूची आइटमों , परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु- संबंधित दोहरे उपयोग की वस्तुओं को हस्तांतरित करने की सुविधा के लिए आईएनआईएफसीआईआरसी/254/भाग1 और 2 के अनुलग्नक ए और बी में सूचीबद्ध किया है , और आईएईए में सुरक्षित नागरिक परमाणु सुविधाओं का उपयोग किया जाना है ।[5] [6] भाग लेने वाली सरकारों को भारत के साथ किए गए द्विपक्षीय परमाणु समझौतों के बारे में एक- दूसरे को सूचित करना होगा। एनएसजी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में एनएसजी के अध्यक्ष भी भारत के साथ परामर्श करने का हकदार है।[7]

एनएसजी पूर्ण सत्र-2016, जिसमें एनएसजी में भारत का पहला औपचारिक आवेदन किया गया था, भारत सरकार के राजनयिक और नरम शक्ति प्रयासों के बावजूद , भारत सरकार के एनएसजी सदस्यता के प्रश्न पर कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई किए बिना उसे पारित कर दिया था।[8]

सत्र में भारत के एनएसजी के साथ संबंध बनाने की संभावना के साथ 2008 के असैनिक परमाणु सहयोग समझौते पर चर्चा हुई।[9] **एनएसजी में भारत का प्रवेश एक विवादास्पद विषय है , यह केवल देश के लिए एनपीटी की सदस्यता की आवश्यकता और एनपीटी के पूर्वाग्रही प्रकृति के भारत द्वारा विरोध के कारण ही नहीं, बल्कि इस तथ्य के कारण भी है कि एनएसजी की उत्पत्ति 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद भारत को रोकने के लिए हुई थी।**[10]

पृष्ठभूमि

भारतीय पक्ष की एनएसजी के साथ संबंध बनाने की कोशिश का अन्य देशों के पक्ष ने लंबे समय तक विरोध किया है। भारत को प्रमुख निर्यात शासनों से बाहर रखा गया है क्योंकि यह पहले से ही अपनी घरेलू परमाणु सुविधाओं पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए सहमत नहीं था। 1 अक्तूबर 2008 को, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 123 परमाणु समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसने एनपीटी से बाहर के ऐसे देश के साथ असैन्य परमाणु व्यापार करने के लिए यह अपवाद बनाया, जो उन्नत था और उन्नत परमाणु क्षमता र खता था। इसने एक विशेष दर्जा हासिल किया क्योंकि 1998 के भारतीय परमाणु परीक्षणों के बाद , अमेरिका ने परमाणु परीक्षणों के लिए दंड के रूप में लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन किया था। नए हाइड एक्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 1954 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम की कुछ आवश्य कताओं को भारत के लिए एक अपवाद बना या और इसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा भी मंजूरी दे दी गई।[11] इस अधिनियम ने भारत के अपने 22 परमाणु रिएक्टरों को अलग करने की सहमति देने पर अपनी नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी विकसित करने में सहायता प्राप्त करने में सुविधा प्रदान की , जिसमें आईएईए द्वारा नियमित निरीक्षण के उद्देश्य से इसके रक्षा परमाणु रिएक्टरों में से 14 असैन्य सुविधाएं शामिल हैं। यह आईएनएफसीआईआरसी/734 में लाए गए सेपरेशन प्लान के अनुसार किया गया था।[12]

भारतीय विदेश और सुरक्षा नीति के लिए 123 समझौते किये जाने का समय एक अच्छा क्षण था। भारत में गैर-नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन के साथ- साथ जल-ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत देश की वर्तमान ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा विकसित करने का अवसर है । हालांकि, लंबे समय में, देश द्वारा पूरी तरह से आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति प्रदान करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय अपकर्ष और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबावों को देखते हुए, भारत द्वारा पेरि स समझौते को औचित्य प्रदान किए जाने से भारतीय पक्ष की प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई, जिसे पक्षों द्वारा2 अक्तूबर, 2016 को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसी) में अपनाया गया था। “भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की ग्रीन हाउस गैस

(जीएचजी) उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक, 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। अन्य परिमाणित लक्ष्य हैं- (क) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) सहित कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की मदद से , 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता प्राप्त करना , और (ख) "2030 तक अतिरिक्त वन और पेड़ों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन सीओ2 के समतुल्य के लिए अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।[13]

एनएसजी सदस्यता के लिए भारत की कोशिश की समय सीमा

- 19 सितंबर 2008 - एनएसजी में भारत को छूट प्रदान करने के लिए बनाए गए अपवादों को भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग पर आईएईए द्वारा जारी किए गए सूचना परिपत्र संख्या 734 दस्तावेज़ में लिखा गया था, जिसे एनएसजी द्वारा अपनाया जाना था।[14]

- 23 मई 2011 - भारत को परमाणु सामग्री नियंत्रण व्यवस्था की तह तक पहुँचाने और असैन्य उद्देश्यों के लिए अन्य परमाणु राज्यों के साथ विनियमित तरीके से परमाणु वाणिज्य में संलग्न होने के लिए एक जिम्मेदार एनडब्ल्यूएस के रूप में स्वीकार करने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने “2011 में नोर्डविजक में आयोजित पूर्ण बैठक में समूह को भारत की सदस्यता के मुद्दे पर विचार करने के लिए “विचार के लिए खाद्य ” पर्चा अग्रेसित किया था । इस पत्र को अन्य एनएनडब्ल्यूएस के साथ साझा न करके अपनी घरेलू परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए भारतीय पक्ष की गारंटी के रूप में देखा गया था।[15] [16]

- 23 जून 2014 - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि की, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत में घरेलू स्तर पर संचालित किसी भी परमाणु- संबंधित गतिविधियों को "अघोषित" और असुरक्षित प्रचार चिंता का विषय नहीं माना जा सकता।[17]

- 25 जुलाई 2014 - भारत ने, भारतीय राजदूत राजीव मिश्रा द्वारा आईएईए के महानिदेशक युकिया अमानो को अनुसमर्थन उपकरण सौंपा।[18]

- भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि 2008 की एनएसजी छूट प्राप्त करने के बावजूद, भारत ने एनएसजी सदस्यता के लिए प्रयास करना जारी रखा, क्योंकि छूट के बावजूद, भारत अब भी एक गैर-सदस्य माना जाता है। पूर्ण एनएसजी सदस्यता प्राप्त होने पर भारत निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेगा। भारतीय असैनिक परमाणु शक्ति को विकसित करने के उद्देश्य को साकार करने में पूंजी, परमाणु ईंधन और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में भारी निवेश होगा।[19]

एनएसजी छूट के बाद एनएसजी के लिए भारतीय प्रयास

हालांकि, यह छूट भारत को परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापार करने की गुंजाइश प्रदान करती है, फिर भी यह अभी तक तदर्थवाद और छूट के दिशानिर्देशों में अचानक संशोधन होने की अनिश्चितता से घिरा है। जिसे केवल एनएसजी का सक्रिय सदस्य बनकर ही सुरक्षित किया जा सकता है, सदस्यता यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी कोई भी नकारात्मक कार्रवाई भारतीय परमाणु उद्योग की निरंतर प्रगति में बाधा न बन सके। इसके अलावा, यह भारत द्वारा विदेशों के साथ किए परमाणु समझौतों को भी सुरक्षित करेगा।[20] यह भारत को एनएसजी में शामिल किए जाने में बहुत मददगार हो सकता है और बदले में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी शासन के लिए दरवाजे खोल सकता है।[21] एनएसजी में भारत का प्रवेश तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने की भारत की उम्मीदों को काफी प्रोत्साहन दे सकता है, जिसे परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भी लाया जा सकता है ताकि ऊर्जा उत्पादन , स्वास्थ्य, रक्षा और रणनीतिक विकास में इसका उपयोग किया जा सके।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भारत के लिए एनएसजी में नियम बनाने का एक हिस्सा होना नियम को मानने की स्थिति में होने से बेहतर है। सदस्यता भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रमों के लिए आवश्यक परमाणु ऊर्जा की निर्बाध पहुंच प्रदान करेगी।[22] पूर्ण सदस्यता भारत को अप्रत्याशितता के तत्व और साथ ही दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उत्पन्न हो सकने वाले परिचर जोखिम से मुक्त करेगी, और बदले में प्रौद्योगिकी, ईंधन और अन्य दोहरे उपयोग की सामग्री में वैश्विक परमाणु व्यापार के लिए निश्चितता लाती है जो घरेलू परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं और बदले में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार को भी मजबूत करेगी।[23]

चूंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2005 में भारत के साथ गहरा रणनीतिक सहयोग शुरू किया था, इसलिए भारत और अमेरिका ने 2008 में 123 भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चूंकि परमाणु ऊर्जा इस नींव की आधारशिला थी, इसलिए 2008 की परमाणु छूट ने एनएनडब्ल्यूएस के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी को साझा करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया। भारत को एनएसजी के सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रयास भी संयुक्त राज्य के निवेशों की रक्षा करने और सामूहिक विनाश (डब्ल्यूएमडी) के हथियारों के प्रसार के उपायों और उनके वितरण तंत्रों के प्रति साझा पारस्परिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इसके कारण अमेरिका ने एनएसजी में भाग लेने वाली सरकारों से , एनएसजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर), वासेनार एग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप सहित मुख्य परमाणु नियंत्रण व्यवस्थाओं में सदस्यता के लिए भारत के औपचारिक अनुरोध को अपना समर्थन देने का आह्वान किया।[24]

क्या भारत एनएसजी की सदस्यता के बिना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शासन में अपना काम कर सकता है?

नीति-निर्माताओं और रणनीतिकारों में से कुछ का मानना है कि भारत को एनएसजी सदस्यता के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है , सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लिए किसी ठोस समयरेखा का अभाव इस दृष्टिकोण के मुख्य कारणों में से एक है। लेखक के साथ राजदूत राकेश सूद की एक बातचीत हुई, राजदूत राकेश सूद ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के

विशेष दूत के रूप में भी काम किया है , उन्होंने कहा कि 2008 की एनएसजी छूट भारत को नागरिक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार और वाणिज्य में संलग्न करने के लिए पर्याप्त है। यह छूट अद्वितीय है क्योंकि यह एनएसजी द्वारा दी गई एकमात्र ऐसी छूट है और यह एनपीटी का एक पक्ष न होने के बावजूद भारत के अनुकरणीय अप्रसार रिकॉर्ड की स्वीकार्यता है। भारत ने एनएसजी के दिशानिर्देशों का पालन करने और तदनुसार अपने निर्यात नियंत्रणों का सामंजस्य बनाने के लिए भी काम किया। 2008 की छूट के बाद एक दर्जन से अधिक देशों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद , इसकी अधिक संभावना नहीं है कि एनएसजी अपने 2008 के फैसले को उलट देगा क्योंकि ये देश भी भारत के साथ अपने सहयोग को जारी रखना चाहेंगे। इसलिए, एनएसजी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए, भारत की सदस्यता की इच्छा राजनीतिक कारणों से अधिक है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में भारत की विशेष स्थिति की एक और स्वीकृति और मान्यता को भी चिह्नित करता है।[25]

भारत के पूर्व रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) में आयोजित 10वें एशियाई सुरक्षा सम्मेलन के मुख्य भाषण में उल्लेख किया कि भारत को यह एनएसजी छूट उन्नत परमाणु क्षमता वाले एक जिम्मेदार देश के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बाद ही दी गई है।[26] भारत के तीन चरण के स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम की यूरेनियम आवश्यकता को बनाए रखने के लिए भी एनएसजी की सदस्यता मांगी जाती है, जिसे 1950 के मध्य में डॉ. होमी भाभा ने भारत के सीमित यूरेनियम और परमाणु ईंधन के रूप में थोरियम के विशाल भंडार का उपयोग करके तैयार किया था। पहले चरण में यूरेनियम और भारी जल रिएक्टर का उपयोग किया गया था , जो अगले चरण के लिए बिजली और प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए मॉडरेटर और कूलर के रूप में था। [27] दूसरे चरण में पुनर्वितरण सुविधा में खर्च किए गए ईंधन का उपयोग देखा गया , जहां प्लूटोनियम को अलग किया गया और फास्ट ब्रीड रिएक्टर में उसका उपयोग किया गया। आवश्यक प्लूटोनियम के उत्पादन के बाद , तीसरे चरण में यूरेनियम का उत्पादन करने के लिए रिएक्टर में थोरियम का उपयोग किया जा ता है। इसलिए, एक पूर्ण परमाणु ईंधन चक्र बनाया जाता है। इस प्रकार केवल प्रथम चरण में ईंधन चक्र को बनाए रखने के लिए भारत को बाहर से यूरेनियम की आवश्यकता है। [28] तीन चरण का परमाणु चक्र कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन था।

एमटीसीआर और अन्य प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्थाएं

जून 2016 में वियना में बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार (एचसीओसी) के खिलाफ हेग कोड ऑफ कंडक्ट पर हस्ताक्षर करने का भारत का निर्णय, भारत के अप्रसार के अनुकरणीय रिकॉर्ड का एक और उदाहरण है, जो वैश्विक निरस्त्रीकरण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। [29] हेग आचार संहिता डब्ल्यूएमडी के प्रसार को रोकने के लिए एक स्वैच्छिक आत्मविश्वास- निर्माण और पारदर्शिता तंत्र है। इस सदस्यता को एमटीसीआर सदस्यता के ट्रैक पर अग्रणी भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में देखा गया था, जिसे अंततः भारत ने 27 जून, 2016 को हासिल किया, और संगठन में शामिल होने वाला 35वाँ सदस्य बन गया।[30] यह उच्च मिसाइल प्रौद्योगिकियों, वितरण प्रणालियों और अंतरिक्ष से संबंधित विशेषज्ञता तक पहुंच

प्राप्त करने में बहुत सहायता कर सकता है। एमटीसीआर की सदस्यता भारत को काम करने और मेक इन इंडिया परियोजना जैसे स्वदेशी रक्षा क्षेत्र और अन्य पहलों को विकसित करने के पुनर्निमाण में निवेश करने और संलग्न होने का अवसर प्रदान करती है।[31] इसके अतिरिक्त, यह भारत को "उप-प्रणालियों, उपग्रहों और वाणिज्यिक सेवाओं आदि के निर्यात " आदि जैसे अपने वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों के विस्तार में भी लाभान्वित करेगी।[32]

एनएसजी सदस्यता के लिए भारत की कोशिश पर अंतर्राष्ट्रीय राय

भारत के लिए 2008 के परमाणु छूट के बाद, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रूस, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम , जैसे अन्य देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।[33] ये समझौते परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा मुद्दों के साथ ही रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन पर ज्ञान का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं।

भारत को अपनी एनएसजी सदस्यता के लिए, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, चीन, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की जैसे देशों के विरोध का साम ना करना पड़ा। यह केवल भारत के एनपीटी का एक पक्ष नहीं होने के कारण नहीं था, बल्कि कई अलग-अलग कारण विपक्षी आवाजों में योगदान दे रहे थे। दक्षिण अफ्रीका ने 1994 में अपने परमाणु कार्यक्रम को निलंबित कर दिया था, जो सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण का विरोध करता है।[34] लेकिन 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान जारी किए गए भारत- दक्षिण अफ्रीका संयुक्त वक्तव्य में , उन्होंने भारत की सदस्यता की मांग[35] के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। न्यूज़ीलैंड और आयरलैंड के अन्य लोग एनएसजी में भारत और अन्य गैर-एनपीटी देशों के प्रवेश के मानदंडों पर चर्चा करना चाहते थे , जबकि ब्राजील ने सदस्यता के लिए गैर-भेदभावपूर्ण मानदंडों पर जोर देने के आधार पर भारत की सदस्यता का विरोध किया था। लेकिन अक्तूबर 2016 में ब्राजील के राष्ट्रपति श्री मिशेल टेमर और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई बैठक में, ब्राजील ने एनएसजी में भारत की सदस्यता के दावे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता की।[36] वर्ष 2013 में, भारत के राष्ट्रपति ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की स दस्यता सुरक्षित करने के लिए तुर्की से भी मदद मांगी। तुर्की के तत्कालीन विदेश मंत्री अहमत दावुतोग्लू ने भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भारत की एनएसजी सदस्यता के लिए तुर्की का समर्थन व्यक्त किया।[37] हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन की भारत यात्रा में भी इस कथन को दोहराया गया था।[38]

नामीबिया के राष्ट्रपति हिफिकपुन्ने पोहाम्बा ने 2009 में, भारत का दौरा करते समय पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की थी कि नामीबिया परमाणु ऊर्जा के मामलों में भारत के साथ शांतिपूर्ण सहयोग करेगा , नामीबिया दुनिया भर में यूरेनियम का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। हालाँकि, भारत के एनपीटी का सदस्य होने और नामीबिया के पेलिंडाबा संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते , जो अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि है , अफ्रीकी संघ द्वारा व्यापार को रोक दिया गया है। एनएसजी सदस्यता इस

मुद्दे को हल करेगी और भारत को अपने घरेलू परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम प्राप्त करने के योग्य बनाएगी।[39]

चीन ने भी भारत की सदस्यता का विरोध किया था, हालाँकि उसने चीन द्वारा एनएसजी में प्रवेश करने से पहले इस्लामाबाद के साथ की गई संधि के आधार पर, एक "ग्रैंडफादर क्लॉज" के एवज में पाकिस्तान को दो परमाणु रिएक्टर निर्यात करने का फैसला किया था ।[40] एनएनडब्ल्यूएस को परमाणु सामग्री की बिक्री को रोकने वाले एनएसजी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके की गई इस कार्रवाई पर काफी प्रतिक्रिया हुई थी।[41] चीन की ओर से हुई यह कार्रवाई , दोनों सहयोगियों, चीन और पाकिस्तान के बीच निकटता के स्तर को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, इस तरह की कार्रवाई भारत को दक्षिण एशिया और उसके पड़ोस में आतंकवाद और अस्थिरता के मुद्दों से निपटने के लिए बांधे रखेगी, और अपने असैनिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को आगे बढ़ाने में संलग्न करेगी। इस प्रकार एनएसजी में प्रवेश पाने के लिए भारत और पाकिस्तान के आवेदनों को एक ही स्तर पर रखने का तर्क एक त्रुटिपूर्ण तर्क है, जिसमें उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान के अस्पष्ट अप्रसार रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है। 2016 में दक्षिण कोरिया में आयोजित एनएसजी के 26वें पूर्ण सत्र की तैयारियों के लिए , भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश सचिव सुब्रह्मण्यम जयशंकर , एनएसजी में भारत की सदस्यता के इस मुद्दे पर ची न के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि, समर्थन हासिल करने के कूटनीतिक प्रयासों और भारत द्वारा अनुमोदन के लिए औपचारिक रूप से विचार करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद, चीन के नेतृत्व में राष्ट्रों के एक छोटे समूह ने इसका विरोध किया। चीन ने "गैर-एनपीटी हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के गैर- प्रवेश" से अलग रहने के लिए जो तर्क दिया है , वह भारत के एनएसजी में नए सदस्यों को स्वीकार करने के लिए दो-दिशानिर्देशों को स्वीकार करने के लिए आगे आने पर है। पहला कदम "गैर-एनपीटी राज्यों के लिए लागू गैर- भेदभावपूर्ण फार्मूले पर एक समझौते का पता लगाने और उस तक पहुंचने और दूसरे चरण में देश की विशिष्ट स दस्यता के मुद्दों को आगे बढ़ाने " पर जोर देता है।[42]

सुरक्षित रूप से यह माना जा सकता है कि चीन द्वारा भारतीय आवेदन का समर्थन कराने का कोई भी प्रयास न केवल अपने आप में एक कठिन प्रयास होगा, बल्कि इसका परिणाम यह भी होगा कि चीन को कूटनीतिक रूप से एक लाभ मिल रहा है क्योंकि चीन पहले से ही एक एनएसजी सदस्य है। चीन 2016 में सियोल के पूर्ण सत्र के दौरान भी चिंतित था कि अमेरिका ओबामा प्रशासन के विदाई उपहार के रूप में भारत की सदस्यता को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि, भारत की सदस्यता की असफल मांग को देखते हुए, भारत सरकार को डोनाल्ड ट्रम्प के अंतर्गत नए अमेरिकी प्रशासन के साथ एक स्थिर और स्वस्थ संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही एनएसजी और अन्य प्रौद्योगिकी तथा ईंधन नियंत्रण व्यवस्था के लिए एक पूर्ण सदस्यता हासिल करने के प्रयासों को जारी रखना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते से पहले की तात्कालिक अवधि में 2008 की परमाणु छूट के आलोक में और परमाणु ऊर्जा के हस्तांतरण और विकास के लिए अन्य विभिन्न देशों के साथ परमाणु सहयोग समझौते के बाद, एनएसजी की सदस्यता को भारतीय राज्य की परमाणु आकांक्षाओं के अतिरिक्त महान मूल्य नहीं भी माना जा सकता है । हालाँकि, भारत सरकार द्वारा एनएसजी सदस्यता के मुद्दे पर पहले ही बहुत बड़ी राजनीतिक पूंजी लगाई गई है, इसलिए सदस्यता हासिल करना भारत की छवि को एक प्रमुख परमाणु शक्ति के रूप में बढ़ाने में सहायक होगा। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में मानक बनाने वाले शासन का हिस्सा बनने के लिए बढ़ावा देगा। मार्च 2017 में बीजिंग में भारत और चीन के बीच हुई रणनीतिक वार्ता का हालिया दौ र एनएसजी की सदस्यता हासिल करने के लिए भारत द्वारा चीन से समर्थन हासिल करने के मुद्दे पर केंद्रित था। [43] इस प्रकार, भारत सरकार को भविष्य के सत्रों में नए दबाव के साथ एनएसजी की सदस्यता हासिल करने के अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए। फिर भी, पहले की गई चर्चा के अनुसार, एनएसजी का एक हिस्सा होने के नाते ऐसा कुछ नहीं है, जो भारत के बिना नहीं हो सकता, लेकिन सदस्यता प्राप्त करना भारत के परमाणु व्यापार कार्टेल के अंदर एक आवाज होने में सहायता करने में कुछ हद तक फायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त, चूंकि एनएसजी की सदस्यता के लिए मोदी सरकार द्वारा बहुत सारी राजनीतिक पूंजी का निवेश किया गया है, सदस्यता प्राप्त करने से भारतीय कूटनीति को बढ़ावा मिलेगा।

***

* *शाइस्ता निशात अहमद, भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्येता हैं*

*

अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।

पादटिप्पणियां :

1 Rajesh Rajagopalanand Atul Mishra, "*Nuclear South Asia: Key Words and Concepts*", New Delhi and Abingdon: Routledge, 2014: 212.

2 International Atomic Energy Agency, "Communication Received from the Permanent Mission of Argentina to the International Atomic Energy on behalf of the Participating Governments of the Nuclear Suppliers Group", INFCIRC/539/Rev.6, जनवरी 26, 2015, https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc539r6.pdf (मई 16, 2017 को अभिगम्य).

3 पूर्वोक्त

4 Nuclear Suppliers Group, "Nuclear Suppliers Group Plenary Meeting", Press Statements, Aspen, मई 10-11, 2001, http://www.nsg-online.org/images/Files/Documents-page/Public_Statements/2001-2-Press.pdf (अप्रैल 8, 2017 को अभिगम्य).

5 International Atomic Energy Agency, "Communication Received from the Permanent Mission of the Czech Republic to the International Atomic Energy Agency regarding Certain Member States'

Guidelines for the Export of Nuclear Material, Equipment and Technology", INFCIRC/254/Rev.12/Part 1a, नवम्बर 13, 2013, https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r12p1.pdf (मई 19, 2017 को अभिगम्य).

6 International Atomic Energy Agency, "Communication Received from the Permanent Mission of the Czech Republic to the International Atomic Energy Agency regarding Certain Member States Regarding Guidelines for Transfers of Nuclear-related Dual-use Equipment, Materials, Software and Related Technology", INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r9p2.pdf (मई 19, 2017 को अभिगम्य).

7 International Atomic Energy Agency, 'Communication dated 10 सितम्बर 2008 received from the Permanent Mission of Germany to the Agency regarding a "Statement on Civil Nuclear Cooperation with India"', INFCIRC/734 (Corrected), सितम्बर 19, 2008, https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2008/infcirc734c.pdf (मई 19, 2017 को अभिगम्य).

8 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "Spokesperson's Comments on NSG Plenary Meeting in Seoul", जून 24, 2016, https://www.mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/26949/spokespersons+comments+on+nsg+plenary+meeting+in+seoul (मार्च 14, 2017 को अभिगम्य).

9 Nuclear Suppliers Group, "Plenary Meeting of the Nuclear Suppliers Group, Seoul", Public Statements, Republic of Korea, जून 23-2, 2016, http://www.nuclearsuppliersgroup.org/images/2016_Public_Statement_Final.pdf (मार्च 10, 2017 को अभिगम्य).

10 The NPT was initiated at the first place as a measure against the spread of nuclear weapons and weapon technology and to promote cooperation in the peaceful uses of nuclear energy. Additionally it also attempts to achieve complete disarmament, both in the nuclear and the conventional sense.

11 Sharad Joshi, "A Pause in the Indo-US Nuclear Agreement", *Nuclear Threat Initiative (NTI)*, मई 2, 2008, http://www.nti.org/analysis/articles/pause-indo-us-nuclear-agreement/ (जनवरी 20, 2017 को अभिगम्य).

12 International Atomic Energy Agency, "Communication dated 10 सितम्बर 2008 Received from the Permanent Mission of Germany to the Agency regarding a "Statement on Civil Nuclear Cooperation with India", INFCIRC/734 (Corrected), 19 सितम्बर 2008, https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2008/infcirc734c.pdf (मई 19, 2017 को अभिगम्य).

13 Press Information Bureau, भारत सरकार, "India's Green Foot Prints hog International Limelight", Special Service and Features, मई 2, 2017, http://pib.nic.in/newsite/printrelease.aspx?relid=161444 (मई 9, 2017 को अभिगम्य).

14 International Atomic Energy Agency, 'Communication dated 10 सितम्बर 2008 received from the Permanent Mission of Germany to the Agency regarding a "Statement on Civil Nuclear Cooperation with India"', INFCIRC/734 (Corrected), सितम्बर 19, 2008, https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2008/infcirc734c.pdf (मई 19, 2017 को अभिगम्य).

15 Arms Control Association, United States Communication – "Food for Thought" Paper on Indian NSG Membership, NSG Confidential, मई 23, 2011, https://www.armscontrol.org/system/files/nsg1130.pdf (अप्रैल 14, 2017 को अभिगम्य).

16 G. Balachandran, "India should be Wary of Additions to the 2008 Criteria", *Indian Foreign Affairs Journal*, 11 (3), जुलाई -सितम्बर 2016, http://associationdiplomats.org/Publications/ifaj/Vol11/11.3/11.3-DEBATE.pdf (जनवरी 23, 2017 को अभिगम्य).

17 Aabha Dixit, "India's Additional Protocol Enters In to Force", *International Atomic Energy Agency*, जुलाई 25, 2014, https://www.iaea.org/newscenter/news/indias-additional-protocol-enters-force (जनवरी 23, 2017 को अभिगम्य).

18 पूर्वोक्त

19 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "English Rendering of Annual Press Conference by External Affairs Minister", Media Centre/ Documents, जून 19, 2016, http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/26955/English_Rendering_of_Annual_Press_Conference_by_External_Affairs_Minister_जून _19 2016 (अप्रैल 22, 2017 को अभिगम्य).

20 G. Balachandran and Shruti Pandalai, "India's NSG Bid: Let's Set the Record Straight", *Institute for Defence Studies and Analysis*, जुलाई 6, 2016, http://www.idsa.in/issuebrief/india-nsg-bid_balachandran-spandalai_060716 (अप्रैल 21, 2017 को अभिगम्य).

21 Montgomery Blah, "Commitments Inked in Paris: Can India Deliver by 2020?" *India Quarterly*, 72 (4): 343-360, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0974928416671589 (अप्रैल 2, 2017 को अभिगम्य).

22 Press Information Bureau, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "Nuclear Suppliers Group Membership", जुलाई 20, 2016, http://pib.nic.in/newsite/mbErel.aspx?relid=147375 (मई 25, 2017 को अभिगम्य).

23 Department of Atomic Energy, भारत सरकार , "Effect of Non-Inclusion In NSG on Energy Production", *Rajya Sabha, Unstarred Question No. 405,* by Dr. Kanwar Deep Singh to Prime

Minister", जुलाई 21, 2016, http://dae.nic.in/writereaddata/parl/monsoon2016/rsus405.pdf (मई 19 को अभिगम्य).

24 Praveen Swami, "What are MTCR and NSG, and Why does India want to be Their Part", *The Indian Express*, जून 10, 2016, http://indianexpress.com/article/explained/narendra-modi-us-visit-mtcr-nsg-obama-us-congress-2844186/ (अप्रैल 25, 2017 को अभिगम्य).

25 Rakesh Sood, Interview, by the author, interview conducted in the Observer Research Foundation, 20 Rouse Avenue Institutional Area Road, New Delhi, मई 3, 2017 (Time 16:30 hours), Delhi, मई 3, 2017.

26 Minister of External Affairs, भारत सरकार, "Key Note Address by External Affairs Minister at the IDSA 10th Asian Security Conference", फरवरी 5, 2008, https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/1492/key+note+address+by+external+affairs+minister+at+the+idsa+10th+asian+security+conference (मार्च 18, 2017 को अभिगम्य).

27 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "Frequently Asked Questions on the India-US Agreement for Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy", नवम्बर 1, 2008, https://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/19149_Frequently_Asked_Questions_01-11-2008.pdf (अप्रैल 25, 2017 को अभिगम्य).

28 Department of Atomic Energy, भारत सरकार, "Anu Shakti: Atomic Energy in India: Strategy for Nuclear Energy", *Bhabha Atomic Research Centre*, http://barc.gov.in/about/anushakti_sne.html (अप्रैल 25, 2017 को अभिगम्य).

29 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "India Joins Hague Code of Conduct", जून 2, 2016, http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/26863/India_Joins_Hague_Code_of_Conduct (जनवरी 30, 2017 को अभिगम्य).

30 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "India Joins Missile Technology Control Regime", जून 27, 2016, http://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/26953/India_joins_Missile_Technology_Control_Regime (फरवरी 2, 2017 को अभिगम्य).

31 Press Information Bureau, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "India as 35th member of Missile Technology Control Regime", जुलाई 20, 2016,http://pib.nic.in/newsite/mbErel.aspx?relid=147380 (मई 31, 2017 को अभिगम्य).

32 Press Information Bureau, Department of Space, भारत सरकार, "Benefits from MTCR for Space Programme", जुलाई 21, 2016, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=147438 (मई 31, 2017 को अभिगम्य).

33 Department of Atomic Energy, भारत सरकार , "Important Agreements", http://www.dae.nic.in/?q=node/75 (जनवरी 27, 2017 को अभिगम्य).

34 Ruchita Beri, “India’s Entry into NSG: Why is South Africa holding Out?”, IDSA Comment, जून 15, 2016, http://www.idsa.in/idsacomments/india-entry-into-nsg-why-is-south-africa-holding-out_rberi_150616 (फरवरी 5, 2017 को अभिगम्य).
35 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, “India-South Africa Joint Statement During the Visit of Prime Minister to South Africa, जुलाई 8, 2016, http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/27001/indiasouth+africa+joint+statement+during+the+visit+of+prime+minister+to+south+africa+जुलाई +08+2016 (मार्च 19, 2017 को अभिगम्य).

36 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, “India-Brazil Joint Statement during the Visit of the Brazilian President to India”, अक्तूबर 17, 2016, http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/27499/indiabrazil+joint+statement+during+the+visit+of+president+of+brazil+to+india (मार्च 18 2017 को अभिगम्य).

37 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, Media Center Documents, “Transcript of Media Briefing by President En route from Istanbul”, अक्तूबर 7, 2013, http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/22300/transcript+of+media+briefing+by+president+en+route+from+isanbul+अक्तूबर +7+2013 (मई 31, 2017 को अभिगम्य).

38 IANS, “No Objection to India’s NSG Membership: Turkish Officials”, *The Economic Times*, अप्रैल 27, 2017
http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/no-objection-to-indias-nsg-membership-turkish-official/articleshow/58397807.cms (अप्रैल 29, 2017 को अभिगम्य).
39 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, “India Namibia Relations”, दिसम्बर 6, 2016
https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Indo-Namibian_Relations__for_Website__-2.1.pdf (अप्रैल 30, 2017 को अभिगम्य).

40 Oliver Thranert and Matthias Bieri, “The Nuclear Suppliers Group at the Crossroads”, Center for Security Studies, CSS Analysis in Security Policy, No. 127, फरवरी 2013, http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CSS-Analysis-127-EN.pdf (मई 25, 2017 को अभिगम्य).
41 Sharad Joshi, “The China-Pakistan Nuclear Deal: A Realpolitique Fait Accompli”, *Nuclear Threat Initiative*, दिसम्बर 11, 2011, http://www.nti.org/analysis/articles/china-pakistan-nuclear-deal-realpolitique-fait-accompli-1/ (जनवरी 29, 2017 को अभिगम्य).
42 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “China Supports the Notion of Two-Step Approach within the Nuclear Suppliers Group to Explore a Non-Discriminatory Formula Applicable to all Non-NPT States”, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1397219.shtml (जनवरी 29, 2017 को अभिगम्य).
43 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, “Transcript of Media Briefing by Foreign Secretary following India-China Strategic Dialogue”, फरवरी 22, 2017, http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/28089/Transcript+of+Media+Briefing+by+Foreign+Secretary+following+IndiaChina+Strategic+Dialogue (फरवरी 23, 2017 को अभिगम्य).